

‘‘राइट टू हैल्थ’’ एक्ट पर विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में घमासान

सरकार का कहना था कि मौजूदा योजनाओं में स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अलग कानून की जरूरत नहीं

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2०22 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने, अप्रैल 2०23 में अधिसूचित राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय हुआ और इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस

- कांग्रेस का कहना था कि नियम नहीं बना कर जनता के **स्वास्थ्य** के साथ **खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।**

और सरकार के जवाब की जानकारी भी मांगी।

इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवरसर ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से ठीक पहले बिना पर्याप्त तैयारी के यह अधिनियम लेकर आई थी। नियम नहीं बनाए गए और हितधारकों से समुचित चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम के नियमों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और निर्णय प्रतीक्षित है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना” के तहत 25 लाख रुपये तक का वार्षिक कैशलेस इलाज उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और 217.9 उपचार पैकेज इसमें शामिल हैं। निःशुल्क जांच, दवाइयां, ओपीडी, आर्थोपीडी, आपातकालीन सेवाएं, हीमोडायलिसिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहले से दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है और टेलर तथा प्रचार सामग्री पहले ही वापस ले ली गई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी बताने को कहा कि क्या फिल्म “घूसखोर पंडित” में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है।
कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है।
अदालत ने, “फ्राईडे फिल्मवक्स” द्वारा निर्मित इस फिल्म की टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि फिल्म निर्माता संयम क्यों नहीं बरत सकते।

बेअसर रहा भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की सभी ट्रेड यूनियनं, किसान और मजदूर मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं।
ओडिशा, केरल, तमिलनाडू, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित, कई राज्यों में मिला-जुला असर देखने को मिला।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी

आवाजों को नज़रअंदाज़ किया।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों ने आज दिनभर की हड़ताल कर केन्द्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्रगोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मंच ने दावा किया कि नई श्रम संहिताओं सहित, अन्य मुद्दों के विरोध में सामान्य हड़ताल के लिए 3० करोड़ मजदूरों को संगठित किया जा रहा है।

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के स्थान के बाद केन्द्र सरकार से मंजूरी पाने वाली पहली बड़ी नई परियोजना है। इसके अलावा, पाकल डुल, किरू और रतले बांध परियोजनाओं की भी शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।
भारत सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पानी के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन होगा और देश की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

पाकिस्तान भारत की इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा बांध बनाने से

कायदे, कानून व प्रक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे फर्जी ही कहा जा सकता है।

लेकिन सरकार की हर बात को दोहराने वाला सुविधाजनक गोदी मीडिया यह खबर चला रहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। यह बात निश्चित रूप से हर उस भाजपा समर्थक के दिल और दिमाग में

- ‘‘डिस्टवालिफिकेशन’’ करने के लिए कायदे-कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी कान होना, फिर कार्रवा बना, राहुल गांधी को “डिस्टवालिफाई” करने के प्रयास के असफल होने का।

हो सकता है जो राहुल गांधी से नफरत करता है, और ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। लेकिन बिना सही नियम और

प्रक्रिया के यह सपना हकीकत कैसे बनेगा? यही वह मुख्य सवाल है, जिसे पूछा जाना चाहिए।

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
था कि गांधी के बयानों से संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुई है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, और संसदीय संदर्भ में यह एक गंभीर आरोप है।

लेकिन शाम तक परिदृश्य बदलता दिखाई दिया। संसदीय सूत्रों ने संकेत दिया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने, या अयोग्यता से संबंधित किसी प्रस्ताव को संस्थानत समर्थन नहीं मिला। संसदीय कार्यसूची में किसी औपचारिक उल्लेख का न होना इस बात का संकेत था कि इस कदम पर पुनर्विचार किया गया है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीछे हटना कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संतुलन है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली होने के बावजूद, भाजपा के पास वर्तमान लोकसभा में ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ विवादस्पद अनुशासनात्मक कार्रवाई आसानी से की जा सके। ऐसे किसी भी कदम के लिए, सदन प्रबंधन, सहयोगियों के साथ समन्वय और,

सबसे ऊपर, संभावित प्रतिक्रिया का राजनीतिक आकलन आवश्यक होता। एनडीए के व्यापक दायरे के सूत्रों के अनुसार, टीडीपी और जेडी (यू) जैसे प्रमुख सहयोगी दल ऐसे बड़े टकराव से असहज हो सकते हैं, क्योंकि इसे असहमित दबाने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगामी महत्वपूर्ण राज्य विधानसभाओं चुनावों को देखते हुए, गठबंधन का गणित, वैचारिक स्थिति जितना ही महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी अतिशयता पूर्ण कार्रवाई से विपक्ष को एकजुट होने का अवसर मिल सकता था और इस कार्रवाई से गांधी की राष्ट्रीय छवि के और मजबूत हो जाने की सम्भावना थी।

इसके अतिरिक्त, इस पूरी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम में छवि-प्रबंधन का पहलू भी महत्वपूर्ण है। किसी भाषण के हिस्सों को हटाना अध्यक्ष का एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, लेकिन जब यह कदम विवादास्पद राजनीतिक आरोपों से जुड़ता है, तो कभी-कभी वही बात और अधिक फैल जाती है, जिसे निर्यांत्रित

करने की कोशिश की जाती है। डिजिटल युग में, अभिलेखों से हटाए गए अंश अवसर आधिकारिक रिकार्ड से बाहर व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, जिससे संसर्गश्रिण का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े संभावित भविष्य के खुलासों से सम्बन्धित अटकलों ने राजनीतिक माहौल में अनिश्चितता का तत्व जोड़ दिया है। यद्यपि शीर्ष भारतीय नेतृत्व को फंसाने वाले किसी संभावित खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों का प्रसार ही राजनीतिक हलकों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे माहौल में संसदीय टकराव को बढ़ाना अनिश्चित परिणामों वाला दुःसाहस माना जा सकता था।

मोदी सरकार के सामने दृढ़ता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि या स्पष्ट संवैधानिक आधार के, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता समाप्त

करने के सीधे प्रयास को न केवल प्रक्रियात्मक और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने के विपक्षी दलों के आरोपों को भी बल मिल सकता था।

राहुल गांधी के लिए यह प्रकरण उनके विकसित होते संसदीय व्यक्तित्व को रेखांकित करता है, एक ऐसे नेता के रूप में, जो तीखे टकराव से पीछे नहीं हटता। यह रणनीति उन्हें दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ देगी या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। फिलहाल, जो विशेषाधिकार प्रस्ताव आसप्त प्रतीत हो रहा था, वह राजनीतिक दांव-पेंच और संसदीय व्यावहारिकता के टकराव का उदाहरण बन गया है।

निष्कर्षतः, यह प्रकरण समकालीन भारतीय राजनीति की इस व्यापक सच्चाई को उजागर करता है कि लड़ाइयाँ केवल सदन के पटल पर ही नहीं, बल्कि धारणा, गठबंधन प्रबंधन और चुनावी गणित के क्षेत्र में भी लड़ी जाती हैं और कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण कदम वही होता है, जो अंततः उठाया ही नहीं जाता।

मोदी आज नए ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे। जानकारी के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:3० बजे ‘सेवा तीर्थ’

- सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी शाम 6 बजे उद्घाटन होगा।**

बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे।फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हैं।

‘ दिल्ली हवा खाने नहीं आए हैं, राजनीति करने आए हैं’

कर्नाटक के नेता शिवकुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की

- डी के शिवकुमार ने खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की।**
- शिवकुमार की इस मीटिंग के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरु हो गई है।**

हालांकि शिवकुमार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड़ा से मुलाकात पर सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है।

‘दूषित फल-सब्जियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि डेयरियों में पहुंचा हुआ दूध मिलावटी नहीं है। इस दौरान पूर्व महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि पशुओं को ऑक्सिटीसीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध उत्पादन

तालेड़ा के स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका पर हमला किया

बालिका के दादा के अनुसार, उसके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर घाव हैं

- कोटा मैंडिकल कॉलेज में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि बालिका के शरीर पर करीब 20 घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में घाव हो गया, इसलिए श्वसन तंत्र को सुचारु रखने के लिए ट्यूब डाली गई है।**

गए, जहां से बच्चों को कोटा रेफर किया गया है।

बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं। वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा है कि उसके शरीर पर चरेरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को

लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले। मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज करीब 2० के आसपास घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है। इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारु रखा जा सके।बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित, कई जगह पर घाव के निशान हैं।

भारत में निपाह वायरस से पहली मौत

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दो मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इस साल निपाह वायरस से यह पहली मौत है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 11 जनवरी 2०26 को पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए निपाह संक्रमण के दो

संक्रमित नर्सिंग स्टाफ नॉर्थ 24 पराना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल थीं। पुरुष नर्स इलाज के दौरान ठीक हो गया, लेकिन महिला को उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महिलाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं प्रमुख दलों ने भी उन्हें केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नामांकन दिए हैं। 2०26 के चुनाव महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट और जबरदस्त गिरावट दर्शाते हैं और बांग्लादेश की राजनीति में लैंगिक समानता के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुरुवार को चुनाव के दिन ढाका में भारी मतदान देखा गया, जहां जमात और बीएनपी के बीच मुकाबला चुनावी परिदृश्य को परिभाषित करता नजर आया। जनरेशन-ज़ैड आंदोलन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आईं।

श्रीलंका के लिए हवाई उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि

भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलम्बो में होने वाले मुकाबले के कारण यह वृद्धि हुई है

- बड़ी संख्या में लोग कोलम्बो जा रहे हैं इस वजह से चेन्नई से कोलम्बो की हवाई टिकट, जो 7,127 रुपये की होती थी, के दाम बढ़कर 22 से 25 हजार तक पहुँच गए हैं।**

किराया सामान्यतः कम रहता है। इसी वजह से चेन्नई से श्रीलंका जाने वाले यात्रियों की संख्या आमतौर पर अधिक रहती है।

सामान्य दिनों में चेन्नई-श्रीलंका के बीच हवाई किराया लगभग 7,127 रुपये होता है, लेकिन 13 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास का किराया 22,073 रुपये से 25,2०7 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया

42,231 रुपये तक हो गया है। 14 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस का किराया 2०,7०8 रुपये से 25,2०7 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 35,217 रुपये तक बढ़ गया है। मैच के दिन यानी, 15 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस में किराया 18,283 रुपये से 19,464 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस में 28,660 रुपये से 42,231 रुपये तक निर्धारित किया गया है। केवल चेन्नई ही नहीं,

नार्थ कोरिया के किम जोंग उन ने अपनी बेटी को वारिस बनाया

व्योंगयांग, 12 फरवरी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपनी बेटी जू-ए को अपना वारिस चुन लिया है। साउथ कोरिया की जासूसी एजेंसी (एनआईएस) ने गुरुवार को देश के संसदों के सामने यह दावा किया। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस (एनआईएस) ने कहा कि उनके इस दावे के पीछे कई चीजों को आधार बनाया गया है। इनमें उत्तर कोरिया के सरकारी कार्यक्रमों में जू ऐ की बढ़ ती उपस्थिति एक अमर वजह है। इससे लगता है कि किम ने अपने वारिस पसंदा ले लिया है। एनआईएस ने कहा है कि उनकी इस पर नजर होगी कि जू-ए इस महीने के आखिर में नॉर्थ कोरिया की पार्टी कांग्रेस में शामिल होंगी या नहीं। यह बड़ा पॉलिटिकल इवेंट पांच साल में एक बार होता है। टीनएज जू-ऐ का इस कार्यक्रम में आना इस बात की तस्दीक होगी कि वे इस सालने वाली अपनी परिवार की चौथी पीढ़ी बनने जा रही है।

हिंसा व हत्याओं के वातावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच वोटों के लिए मुकाबला हुआ। मतदान प्रक्रिया बीएनपी और जमात के समर्थकों के बीच झड़पों में हुई।

पहले, शेख हसीना के शासनकाल में बीएनपी और जमात ने चुनाव लड़ने के लिए आपस में गठजोड़ किया था। पर अब अवाामी लीग के मैदान में न होने से ये दोनों कट्टरपंथी दल अब एक-दूसरे से अलग हो गए हैं और सत्ता पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धी कर रहे हैं। जमात एक इस्लामी झुकाव वाला बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है।

भारत के लिए ये दोनों दल एक तरह से “हांब्सन चैंडस” प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दोनों ही मूल रूप से भारत-विरोधी हैं और दोनों ने देश में बचे हुए हिंदुओं को बाहर निकालने की दिशा में काम किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार मतदान की सफलता का दावा कर रही है और एक नई शुरुआत की आशा व्यक्त कर रही है।

^[1] राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वरुण प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोटली शांतिपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdutr@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायका हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाणा हाउस, हनुमान हट्या, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, सेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-ध्रुव बाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी/ 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908